www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 179 | जौनपुर शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

प्रधानमंत्री मोदी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन–1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। वे शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर करीब 1रू30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे। इसके बाद वे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन–1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन भारत के प्रशासनिक शासन संरचना में एक बड़ा बदलाव लाने वाला मील का पत्थर है और यह प्रधानमंत्री के एक मॉडर्न, कुशल, सुलभ और नागरिक–केंद्रित गवर्नेंस इकोसिस्टम बनाने के कमिटमेंट को दिखाता है। दशकों से कई जरूरी सरकारी ऑफिस और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा एरिया में अलग–अलग जगहों पर बने हुए थे और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते थे। इससे ऑपरेशनल खामियां, कोऑर्डिनेशन की चुनौतियां, बढ़ते मेंटेनेंस खर्च और काम न कर पाने लायक स्थिति बनी हुई थी। नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के अंदर प्रशासनिक कार्यों को एक साथ करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय बने हुए हैं, जो पहले अलग–अलग जगहों पर थे। कर्तव्य भवन–1 और 2 में कई मंत्रालय होंगे, जिनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, शिक्षा, संस्कृति, कानून, सूचना व प्रसारण, कृषि व किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय शामिल हैं। ग्रिहा–4 मानदंडों के अनुसार डिजाइन किए गए इन कॉम्प्लेक्स में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, पानी बचाने के तरीके, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और हाई–परफॉर्मेंस बिल्डिंग एनवेलप शामिल हैं। ये उपाय पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को काफी कम करते हैं और परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, दिल्ली में दूसरे एआई समिट में करेंगे शिरकत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के भारत दौरा को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति लूला दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे एआई समिट (19–20 फरवरी) में भाग लेंगे। यह समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नीतिगत समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्राजील के राजकीय दौरे का मुख्य दिन 21 फरवरी होगा। इसी दिन भारत और ब्राजील के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति लूला की मेजबानी भारत की राष्ट्रपति करेंगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति समेत कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उनसे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति लूला के साथ कई मंत्री और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि बिजनेस डेलीगेशन को जोड़ने के लिए अलग–अलग बैठकों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे भारत–ब्राजील आर्थिक साझेदारी को नई गति मिल सके। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है।

समय देगा हर सवाल का जवाब : डिप्टी सीएम

बंगलूरू, (एजेंसी)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। सोनिया गांधी के आवास दस जनपथ से बाहर आने के बाद शिवकुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वह यहां सिर्फ दिल्ली की हवा में सांस लेने नहीं आए हैं, बल्कि राजनीति करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय ही हर बात का जवाब देगा। जब उनसे पूछा गया कि वह प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से किससे मिले, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार ने कहा कि वह सड़क पर खड़े होकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली है, जो जरूरी थे। शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली आने पर उन्हें सभी मामलों की जानकारी देनी होती है और उन्होंने हर विषय पर विस्तार से बात की है। शिवकुमार ने आगे कहा, हमने असम विधानसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक मामलों पर चर्चा की है। उन्होंने वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और अन्य नेताओं के साथ मिलकर असम में कांग्रेस की सरकार लाने की तैयारी पर चर्चा की। शिवकुमार के बयानों से कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल मचने की संभावना है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिवकुमार आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। शिवकुमार के समर्थक विधायक चाहते हैं कि पार्टी का आलाकमान दखल दे और नेतृत्व को लेकर चल रही उलझन को खत्म करे। इसी बीच उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने एक बड़ा बयान दिया।

हर क्षेत्र में निर्णय उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेने चाहिए : मोहन भागवत

नागपुर, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक अलग और सशक्त वेटरिनरी काउंसिल के गठन की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जानवरों और जनसुरक्षा से जुड़े फैसले वेटरिनरी डॉक्टरों और विषय–विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही होने चाहिए। भागवत नागपुर में इंडियन सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस (आईएसएसीपी) के 22वें वार्षिक अधिवेशन और श्रोल ऑफ कैनाइन इन वन हेल्थरू बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड रिजॉल्विंग चौलेंजेजश विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इसका आयोजन आईएसएसीपी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी (एमएएफएसयू), नागपुर और नेशनल एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड रिसर्च (एनएडब्ल्यूएआर) ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन की शुरुआत में भागवत ने कहा, ष्मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई की है। हालांकि मुझे वेटरिनरी क्षेत्र छोड़े 50 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप लोगों जितना ज्ञान अब मेरे पास नहीं है। फिर भी पूर्व छात्र के रूप में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूं।ष उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि–आधारित देश को तब तक लाभ मिलता रहा, जब तक किसान खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन भी करते रहे। मोहन भागवत ने वेटरिनरी पेशे के दायरे को सीमित मानने की सोच को गलत बताते हुए कहा, ष्पहले माना जाता था कि वेटरिनरी डॉक्टरों की भूमिका सीमित है, लेकिन यह सोच सही नहीं है। समाज, जनस्वास्थ्य और नीति निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है।ष दिल्ली में हाल ही में लावारिस कुत्तों को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि बहस दो चरम सीमाओं में बंट गई थी, ष्एक पक्ष कह रहा था कि सभी कुत्तों को मार दो, दूसरा कह रहा था कि उन्हें छुओ भी मत। लेकिन अगर इंसानों को कुत्तों के साथ रहना है, तो यह सोचना होगा कि कैसे साथ रहें।ष उन्होंने वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान पर जोर देते हुए कहा, ष्कुत्तों की संख्या नसबंदी के जरिए नियंत्रित की जा सकती है।

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर दिया जवाब, राज्यसभा में चर्चा जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद का बजट सत्र जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भू–राजनीतिक संघर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अमेरिका के सामने मौजूद चुनौतियों पर भाषण दिया। उनका यह भाषण ऐसे समय आया है जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का जिक्र करने के बाद विपक्ष द्वारा उन्हें बोलने न दिए जाने के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हुई। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं थी, जिसके बाद खुद बिरला ने इसमें सुधार करवा के कार्यवाही करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय बजट 2026–27 पर लोकसभा में हुई सामान्य चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कहा है कि शिक्षा पूरी करने और योग्यता हासिल करने के बाद कौशल सीखने के लिए कहां जाना चाहिए, इस पर इंतजार करने के बजाय, कौशल विकास को शिक्षा में ही शामिल किया जा सकता है। इससे छात्र यह कह सकेंगे कि वे उद्यमी बन सकते हैं और इस तरह का एक विशाल केंद्र किसी भी राज्य के औद्योगिक क्लस्टर के पास स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार, शिक्षा केंद्रों के रूप में ऐसे विशाल उद्यमिता विकास केंद्र किसी भी राज्य में स्थापित किए जा सकते हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं ताकि इस विशाल उच्च शिक्षा केंद्र को बढ़ावा दिया जा सके और छात्र वहां जाकर उद्यमी बन सकें। यह बजट 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट है। इसीलिए इसमें 2026 से 2050 तक के कई विषयों को शामिल किया गया है। हम अगले वित्त आयोग, यानी 16वें वित्त आयोग के नए पंचवर्षीय चक्र की भी शुरुआत कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा। इसलिए, अनुमान काफी हद तक वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के ससम्मान गायन को मध्य प्रदेश में लागू करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर प्रदेश में अब सभी कार्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम् के छह छंद गाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन– गण–मन से पहले सभी कार्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के छह छंदों के गायन का निर्णय लिया है। यह अत्यंत सराहनीय एवं अभूतपूर्व पहल है। इसके जरिए पूरा देश अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीर सेनानियों ने वंदे मातरम् गाते हुए स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ी है और वंदे मातरम् गायन के निर्णय को त्वरित रूप से प्रदेश में लागू कर रही है। गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' को लेकर नए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में अब 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य होगा। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को खड़े होकर गीत का सम्मान करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समय किया जाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'वंदे मातरम्' के पूरे छह छंद बजाए जाएंगे, ताकि गीत का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।–

राहुल गांधी अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के सवाल को लेकर पत्रकारों पर भड़के

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से अपने काम में श्उद्देश्यपूर्ण बने रहनेश और अपने पेशे की पवित्रता बनाए रखने को कहा। राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्तापक्ष की तरफ से लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चर्चाएं थीं। हालांकि, बाद में सत्तापक्ष ने इस प्रस्ताव को लाने से साफ इनकार कर दिया। जब राहुल गांधी से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया, तो वे मीडिया के कुछ लोगों पर भड़क गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ष्आप पूरी तरह से भाजपा के लिए काम नहीं करते। कम से कम थोड़ी श्उद्देश्यपूर्णश रिपोर्टिंग करने की कोशिश करें। आप जिम्मेदार लोग हैं। आप मीडिया वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उद्देश्यपूर्ण रहें। आप हर दिन उनके (भाजपा) दिए गए एक शब्द पर अपना पूरा शो नहीं चला सकते।ष बुधवार को, लोकसभा में उस समय विरोध हुआ जब राहुल गांधी ने सरकार की तीखी आलोचना की, जिसमें उन्होंने विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर करने और भारत माता को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस तीखे हमले का सत्तापक्ष ने विरोध किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भाषा को असंसदीय बताते हुए आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने मांग की कि उनके भाषण को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। बाद में भाजपा सांसदों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बेबुनियाद और गलत इरादे वालेश्दावों से सदन को गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा।

सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं, संविधान की आत्मा है : खड़गे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अक्सर दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करते हैं। अब समय है कि इन बातों को जमीन पर उतारने की ठोस पहल की जाए। सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी में, जब हम सामाजिक विकास, सुधार और एकता की बातें करते हैं, तब ओडिशा की एक घटना हमें आईना दिखाती है। वहां एक आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ इसलिए तीन महीनों से बहिष्कार चल रहा है क्योंकि भोजन एक दलित महिला हेल्पर और कुक द्वारा तैयार किया जा रहा है। समुदाय विशेष के कुछ लोग अपने बच्चों को वह भोजन देने से मना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद गंभीर विषय है, जिस पर वह सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बुनियाद होते हैं। अगर वहां जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी जाएगी, तो उसका सीधा असर बच्चों के मन और उनके भविष्य पर पड़ेगा। छोटे–छोटे बच्चों के सामने जब इस तरह का भेदभाव होता है, तो अनजाने में उनके भीतर भी विभाजन और नफरत के बीज बो दिए जाते हैं। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत शिक्षा के अधिकार की भावना को कमजोर करती है। साथ ही, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह पोषण स्तर को बढ़ाए और जनस्वास्थ्य में सुधार करे। अगर पोषण कार्यक्रम ही जातिगत सोच की भेंट चढ़ जाएं, तो यह राज्य के दायित्व पर भी सवाल खड़ा करता है।

संक्षिप्त खबरें

मजदूरों और किसानों की देशव्यापी हड़ताल से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित

केरल, (एजेंसी)। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान समूहों के आह्वान पर आज देशभर में भारत बंद के तहत व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर और किसान हितों के खिलाफ तथा बड़ी कंपनियों के पक्ष में हैं। इसी के विरोध में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने यह राष्ट्रव्यापी कदम उठाया है जिसे कई किसान संगठनों, छात्र समूहों और युवा संगठनों का भी समर्थन मिला है। आज हो रही हड़ताल के दौरान उठ रही मांगों में मुख्य जोर चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, नए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने पर है। साथ ही मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अधिक धन और मजबूत प्रावधान की मांग भी उठाई जा रही है। श्रमिक संगठनों ने जरूरी सामान, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की भी मांग रखी है। हड़ताल के कारण कई जगह जनजीवन पर असर देखा गया। बैंकिंग, बीमा, डाक, परिवहन, खनन, गैस पाइपलाइन और बिजली जैसे क्षेत्रों में आंशिक बाधा की आशंका पहले ही जताई गई थी।

बांग्लादेश चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी

कोलकाता, (एजेंसी)। बांग्लादेश में आज हो रहे संसदीय चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भारत–बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पूरी सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है और गश्त को तेज कर दिया है। बुधवार रात से ही सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुंदरबन के तटीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर बंगाल के सीमावर्ती जिलों तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। बीएसएफ के पूर्वी कमान मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बांग्लादेश में चुनाव के दौरान संभावित हिंसा और अस्थिरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आशंका जताई जा रही है कि अशांति की स्थिति में अपराधी या संदिग्ध तत्व सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। । सीमा के नदीय और दुर्गम इलाकों में भी गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई गई है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां पहले अवैध गतिविधियों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुंदरबन से सटे वन और समुद्री क्षेत्रों में खास तौर पर निगरानी बढ़ाई गई है।

संपादकीय

पीयूष गोयल की टिप्पणी

यह कहना काफी नहीं है कि व्यापार समझौते पर बातचीत अभी चल रही है और उसे लिखा नहीं गया है। जब ऐसा होगा, तब पूरी जानकारी दी जाएगी। दरअसल, पीयूष गोयल की इस टिप्पणी ने अनिश्चय और बढ़ा दिया है। भारत– अमेरिका ट्रेड डील के बारे में डॉनल्ड ट्रंप की घोषणा से बने अनिश्चय के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आनन–फानन में प्रेस कांफ्रेंस कर किसान एवं अन्य समूहों को आश्वस्त करने की कोशिश की। कहा कि कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाएगा। मगर इससे आशंकाएं दूर नहीं हुईं, तो उसकी वजह वॉशिंगटन से आ रहे बयान हैं। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंग्स और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने बेलाग कहा है कि ट्रेड डील में कृषि शामिल है। यह भी कहा है कि अमेरिका के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों पर भारत शून्य आयात शुल्क लगाएगा। उधर ह्वाइट हाउस की प्रवक्ता केरोलीन लेविट कहा है कि भारत ना सिर्फ रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, बल्कि अमेरिका और संभवतरू वेनेजुएला से भी अधिक मात्रा में तेल खरीदेगा। ये वही बातें हैं, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। इसलिए इन मुद्दों पर दो–टूक बयान की जरूरत है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि व्यापार समझौते के कई पहलुओं पर बातचीत चल रही है और उसे अभी लिखा नहीं गया है। जब ऐसा होगा, तब पूरी जानकारी दी जाएगी। दरअसल, गोयल की इस टिप्पणी ने प्रकरण पर और भी धुंध डाल दी है। क्या बिना डील संपन्न हुए ट्रंप ने एलान कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे दिया? ऐसा हुआ, तो उससे दोनों देशों के सर्वोच्च नेतृत्व की छवि और भी खराब होगी। फिर क्या भारत ऐसा आश्वासन लेने में सफल रहा है कि ट्रंप आगे चल कर ब्रिक्स़ की भारत की सदस्यता और ईरान जैसे देशों से व्यापारिक संबंध रखने को मुद्दा नहीं बनाएंगे? हाल में दक्षिण कोरिया से डील होने के बावजूद ट्रंप ने यह कर उस पर 25 फीसदी नया टैरिफ लगा दिया कि वह समझौते पर ठीक से अमल नहीं कर रहा है। ट्रंप के व्यवहार में ऐसी अस्थिरताएं भरी–पड़ी हैं। भारत सरकार का कर्त्तव्य इन तमाम पहलुओं का आकलन करते हुए आगे बढ़ना और देशवासियों को इस संबंध में अवगत रखना होना चाहिए। मगर फिलहाल आधी–अधूरी जानकारियों के आधार पर जश्न का माहौल बनाने की कोशिश होती हम देख रहे हैं।

पैन इंडिया हिंदुत्व की राजनीति

अजीत द्विवेदी

राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिहाज से यह बहुत दिलचस्प समय दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करने की बेहद आक्रामक राजनीति कर रही है। उसने 80 और 20 वाली राजनीति को उत्तर प्रदेश की सीमा से निकाल कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरे देश में आजमाने की राजनीति शुरू की है तो दूसरी ओर प्रादेशिक पार्टियों के पास इसकी काट के लिए सिर्फ भाषायी और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा दिख रहा है। कांग्रेस इस पूरे विमर्श से बाहर हो गई दिखती है। ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस वैचारिक धरातल पर अपनी राजनीतिक रणनीति बनाए। तभी देश का राजनीतिक मुकाबला भाजपा बनाम प्रादेशिक पार्टियों का बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी एक परीक्षा हुई है और भाजपा ने मराठी मानुष की पहचान की उद्धव और राज ठाकरे की राजनीति को बुरी तरह से परास्त किया। ध्यान रहे भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति के प्रत्युत्तर के तौर पर ही उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का साथ छोड़ा और राज ठाकरे से हाथ मिलाया। उद्धव नरम तो राज ठाकरे गरम राजनीति कर रहे थे। राज ठाकरे ने उत्तर और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जहर उगला तो गुजरातियों के खिलाफ भी जबरदस्त आक्रामकता दिखलाई। लेकिन चुनाव जीतने के लिहाज से यह राजनीति कम पड़ गई। मुंबई में तो फिर भी उद्धव ठाकरे की जमीन कुछ बची लेकिन वहां से बाहर उनकी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। बृहन्नमुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के चुनाव से भाषायी और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति की सीमाएं उजागर हुई हैं। हालांकि मुंबई या किसी अन्य महानगर में पहचान की राजनीति की विफलता के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि पूरे प्रदेश में यह राजनीति विफल हो जाएगी। इसका कारण यह है कि महानगरों की जनसंख्या संरचना काफी बदल गई है। मुंबई जैसे महानगर में 25 फीसदी के करीब आबादी उत्तर भारतीयों की है। लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के आधार पर चुनाव हो तो नतीजे अलग हो सकते हैं। तभी भाजपा भी मराठी और हिंदुत्व दोनों अस्मिताओं को एक साथ लेकर चलती है। बहरहाल, इस राजनीति की पड़ताल अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में होने वाली है। ये पांचों राज्य भाषायी और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति वाले राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता का मुद्दा है तो असम में भाषा और संस्कृति दोनों राजनीतिक संघर्ष का विषय बने हैं। उधर तमिलनाडु में भाषायी और क्षेत्रीय दोनों अस्मिता का मुद्दा है तो केरल में अब जाकर सत्तारूढ़ लेफ्ट पार्टी ने मलयालम भाषा की अस्मिता को राजनीति में आजमाने का फैसला किया है। राज्य की लेफ्ट मोर्चा की सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से हिंदी थोपे जाने का मुद्दा उठाया है और मलयालम भाषा बिल पेश किया है, जिसका मकसद मलयालम को नंबर एक और पहली भाषा बनाना है। हालांकि इसे लेकर हिंदी की बजाय कन्नड़ से उसका टकराव शुरू हो गया है। कर्नाटक से लगती सीमा के पास बड़ा इलाका ऐसा है, जहां केरल के लोग कन्नड़ बोलते हैं। खैर यह स्थानीय मामला है, जिसे वही के स्तर पर सुलझाया जाएगा। लेकिन केरल में मलयालम भाषा का मुद्दा बनना यह दिखाता है कि पहचान की राजनीति किस दौर में पहुंच गई है और भाजपा के हिंदुत्व व विकास के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए पार्टियां किस हद तक इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा की बढ़ती ताकत से आशंकित हैं। इसलिए वे भाजपा के हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए इस बार सिर्फ बांग्ला भाषा, अस्मिता व संस्कृति के नैरेटिव पर भरोसा नहीं कर रही हैं, बल्कि उसमें हिंदुत्व का तड़का भी लगा रही हैं। उन्होंने बुनियादी रूप से बांग्ला अस्मिता का मुद्दा बनाया है और बांग्ला भाषियों पर दूसरे राज्यों में हो रहे कथित उत्पीड़न को बार बार उठा रही हैं। लेकिन उनको इसकी सीमा का पता है क्योंकि यह मुद्दा उठाने के बावजूद पिछले सात–आठ साल में भाजपा 40 फीसदी वोट तक पहुंच गई है और यह बात ममता बनर्जी को चिंता में डाले हुए है। इसलिए उन्होंने इस बार हिंदुत्व का मुद्दा उसमें जोड़ दिया है। उन्होंने न्यू कोलकाता टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी है, जहां सरकार 332 करोड़ रुपए में सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर बनवाएगी। इसी तरह सिलिगुड़ी में सबसे बड़े महाकाल मंदिर की नींव उन्होंने रखी। इस मंदिर पर करीब चार सौ करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसकी नींव रखते हुए ममता ने जितनी बार श्हर हर महादेव्य और श्रक्षा करो महादेव्य के नारे लगाए उससे नरेंद्र मोदी के काशी में दिए जाने वाले भाषण याद आ गए। इससे पहले ममता दीघा में जगन्नाथ धाम बनवा चुकी हैं। उन्होंने दुर्गापूजा में पंडालों को पहले से ज्यादा पैसे बांटे हैं। सो, वे भाषायी और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ रही हैं ताकि भाजपा का मुकाबला कर सकें। भाजपा महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे चुनाव लड़ती है।

तारिक की बीएनपी नहीं उस पार्टी का अब होगा शासन

अभिनय

12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद यह बांग्लादेश में होने वाला पहला चुनाव है। शेख हसीना जैसे आपको पहले भी पता है वहां पे जब हलचल हुई तो उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। आवामी लीग बांग्लादेश में बैन है। क्योंकि ये कहा गया कि बांग्लादेश का युवा एक नया सिस्टम चाहता था। नया चेहरा चाहता था। लेकिन चुनावी मैदान में दो पुरानी पार्टियां ही अभी दिख रही हैं। बड़े प्लेयर्स के रूप में बीएनपी और जमात। बीएनपी के नेता तारिक उस राजनीतिक परिवार से हैं जिसने दशकों दशक बांग्लादेश की राजनीति पर गहरी पकड़ बनाकर रखी है। दूसरी तरफ हैं 67 साल के डॉ. शफीक उर रहमान। इनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक भी महिला उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा है। बांग्लादेश में आम चुनाव और जनमत संग्रह कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण माने जा रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब इस पड़ोसी देश की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दो दशकों तक सत्ता में रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश से बाहर है और उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक है। वहीं, बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी की नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो चुका है। इन चुनावों में मौजूद 51 राजनीतिक दलों में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात–ए–इस्लामी के बीच है। इन दोनों ही दलों ने कई छोटे–छोटे दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किए हैं। जमात–ए–इस्लामी 11 दलों के गठबंधन की अगुआई कर रही है। इसमें छात्र के समर्थन से बनी नैशनल सिटिजन पार्टी भी शामिल है, जो शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से निकली है। स्थानीय सर्वे में बीएनपी जीत सकती है। हालांकि जमात को भी काफी लोकप्रिय बताया जा रहा है। 170 मिलियन 17 करोड़ की आबादी वाला ये देश 12 फरवरी को वोट देने वाला है। 300 सीटों पर चुनाव होगा और लगभग 2000 उम्मीदवार इन सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला काटे का है। देश की राजधानी ढाका में 9 फरवरी को चुनावी माहौल पूरी पीक पर था अपने शहर में हजारों लोग झंडे लहराते हुए रैलियों में पहुंचे। हर पार्टी जनता के उस आंदोलन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी जिसने कभी शेख हसीना को राजनीति से बाहर किया। 17 साल के इंसाइल के बाद तारीख दिसंबर में देश लौटे हैं। उनके उनकी पार्टी के चुनावी वादे काफी स्ट्रेट हैं। जैसे गरीब परिवारों को पैसे की मदद देना, कोई भी नेता 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री ना रहे। ऐसी बात करना, विदेशी निवेश लाकर देश की इकॉनमी सुधारना और भ्रष्टाचार पर सख्ती। तारिक रहमान का कहना है कि सिर्फ बीएनपी के ही पास देश चलाने का एक्सपीरियंस है। रैलियों में अपने माता–पिता यानी जिया उर रहमान और खालिदा जिया का जिक्र कई बार किया यह कहते हुए कि दोनों ही देश चला चुके हैं और बाकी पार्टियों के पास ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है जो बीएनपी के पास है। तारिक रहमान की पार्टी का सबसे बड़ा मुकाबला जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है। इसके लीडर हैं शफीक उर रहमान। शफीक उर रहमान एक अलग तरह की राजनीतिक छवि रखते हैं। पेशे से सरकारी वो डॉक्टर रह चुके हैं और 2019 में उस वक्त जमात के चीफ बने थे जब पार्टी पर बैन था। दिसंबर 2022 में उन्हें रात के वक्त आतंकवाद से जुड़े इल्जामों में गिरफ्तार किया गया और 15 महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद मार्च 2025 में जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बन गई तो उस केस से शफीक उर रहमान का नाम हटाया गया। इसके बाद से उनके भाषण और रैलियां लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल ढाका की एक बड़ी रैली में गर्मी के कारण मंच पर दो बार बेहोश हो गए थे। लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उठे और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। कहा जब तक अल्लाह मुझे जिंदगी देगा मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। अगर जमात सत्ता में आई तो हम हुक्मरान नहीं जनता के सेवक होंगे। कोई मंत्री जमीन या टैक्स फ्री गाड़ी लेकर नहीं चलेगा। ना वसूली होगी ना भ्रष्टाचार। मैं युवाओं से साफ कहना चाहता हूं हम आपके साथ हैं। शेख हसीना के दौर में कई साल तक जमात पर बैन रहा। लेकिन 2024 में आंदोलन के बाद जब हसीना की सरकार गिर गई तो जमात फिर से पॉलिटिक्स में लौट आया। जमात के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी है। इसे उन्हीं युवाओं ने बनाया है जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जमात ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। पार्टी के बहुत से नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के दौर में मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सजा दी गई थी। हसीना के शासन में 2013 में पार्टी पर प्रतिबंध भी लगा कई सालों के बाद अब बाजी पलट गई है। राजनीतिक बदलाव जमात के पक्ष में है। पार्टी ने किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है और देश का प्रगतिशील वर्ग काफी ज्यादा असहज है। पूर्व में खालिदा की अगुआई वाली

बीएनपी सरकार से भारत के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे। इस दल की कमान अब उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ है, जिन्होंने लौटते ही श्समावेशी बांग्लादेशश का संदेश दिया था। खालिदा के अंतिम संस्कार में भारत से विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी से रिश्तों की नई झलक दिखी थी। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में श्बांग्लादेश फर्स्ट के साथ पया तीस्ता नदियों के पानी के उचित हिस्से का उल्लेख आक्रामक रुख दिखाता है। वहीं, जमात–ए–इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भारत से संबंधों पर सांकेतिक जवाब दिया, जिसका अर्थ निकाला जा रहा है कि अगर उनका दल सत्ता में आता है, तो भारत के प्रति रुख में नरमी ही होगी। संसदीय चुनाव की तरह जनमत संग्रह भी बैलट पेपर से होगा। सवैधानिक सुधारों से जुड़े बीती जुलाई के नैशनल चार्टर पर लोगों को श्हाश या श्नाश में जवाब देना है। अगर जनमत संग्रह पास हुआ तो नवनियुक्त ससद सविधान सभा की तरह काम करेगी और संविधान में बदलाव करेगी। चार्टर के तहत संसद में 100 सदस्यों का उच्च सदन भी बनेगा। पीएम के लिए दो कार्यकाल की सीमा (अधिकतम 10 साल) तय होगी। तटस्थ सरकार के तहत चुनाव कराने, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग का भी प्रस्ताव है। यह सब पहले 270 दिनों में करना होगा। अल्पसख्यकों पर हमलों और पाक से बढ़ती नजदीकी के बीच भारत के लिए बाग्लादेश बड़ी चुनौती से कम नहीं है। शेख हसीना के विरोध को भापने में नाकाम रहा भारत अब पहले से ही वहां सभी पक्षों से संपर्क में है। वहां का राजनीतिक नेतृत्व भी समझता है कि सामान्य संबंधों में ही सबका भला है।

विवादित हो सकते हैं भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के वायदे

नन्तू

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारी देरी के कारण, भारत ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ एक मेगा व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने श्सभी सौदों की जननीश के रूप में ब्रांडेड किया। इस डील से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिगत मोड़ मिलेगा। महीनों की बातचीत और अनिश्चितताओं के बाद पिछले सप्ताहांत भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के पहले हिस्से के सम्पन्न होने पर जो उत्साह था, वह यदि जल्दबाजी में प्रकट नहीं हुआ हो तो शायद बेतुका है, क्योंकि यह अभी भी साफ नहीं है कि रूस और ईरान जैसे देशों को मिलाकर भारत की बहुपक्षीय संबंधों वाली वैश्विक व्यापार और आर्थिक रणनीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया क्या होगा और यह व्यापार समझौते पर कैसे असर डाल सकता है।अमेरिका, जो चीन से सामान का सबसे बड़ा आयातक है, चीन के रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे बड़े अमेरिका विरोधी देशों के साथ मजबूत व्यापार और राजनयिक रिश्तों के बावजूद चीन के प्रति तुलनात्मक रूप से नरम रहा है। रूस के साथ, भारत लंबे समय से असैन्य नाभिकीय और रक्षा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में मजबूत बहुआयामी रिश्ते का आनंद ले रहा है। भारत रूस में तेल की खोज और उत्पादन में भी एक निवेशक है। अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते से इसकी श्स्विंग स्टेटश के तौर पर अपनी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा और विकास के फायदों को बचाते हुए सभी तरफ से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके।यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने आखिरकार भारतीय निर्यात पर श्पारस्परिक टैरिफश को घटाकर 18प्रतिशत करने का फैसला किया है। बदले में, भारत अब अमेरिका से आयातित होने वाली कई चीजों पर लगने वाले करों में कटौती करेगा। इस व्यापार समझौते में अमेरिका ने रूसी खनिज तेल की खरीद पर भारतीय निर्यात पर लगने वाले 25प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ भी खत्म कर दी, हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या इसका मकसद भारत को रूस से तेल खरीदने से पूरी तरह रोकना था। इस समझौते से भारत के दो बड़े निर्यातक ग्रुप को फायदा होगा– एक में कपड़ा, चमड़ा, रसायन, और समुद्री उत्पादन शामिल हैंय और दूसरे में दवाएं और स्मार्टफोन शामिल हैं। ये दोनों ग्रुप अभी अमेरिका को भारत के निर्यात का 56प्रतिशत के हिस्सेदार हैं। इस समझौते से उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादनों के अमेरिका को निर्यात के लिए ज्यादा फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिनमें से 90प्रतिशत से ज्यादा को टैरिफ खत्म करने, 10 सालों में ड्यूटी में कटौती और कोटा के आधार पर कमी जैसी कई छूट मिलेंगी।ऐसा लगता है कि व्यापार सौदा अगले पांच वर्षों में अमेरिका से भारत के आयात के 500 अरब डॉलर तक बढ़ने के बारे में कुछ हद तक आशावादी है। भारत एक अग्रणी व्यापारिक राष्ट्र नहीं है। वैश्विक व्यापारिक राष्ट्रों में, भारत आयातक के रूप में 10वें और निर्यातक के रूप में 13वें स्थान पर है। उच्च मूल्य के निर्मित उत्पादों की इसकी विनिर्माण और खपत क्षमताएं सीमित रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, अमेरिका से भारत के माल आयात का मूल्य केवल लगभग 45.33 अरब डॉलर था। नई रियायतों के बावजूद अगले पांच वर्षों में इन आयातों के 10 गुना से अधिक बढ़कर 500 अरब डॉलर होने की उम्मीद करना अतार्किक लगता है। भारत साल दर साल भारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटे से जूझ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था एक ही देश से इतने बड़े आयात से हिल सकती है जब तक कि भारत अपने वार्षिक व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों से आयात में भारी कटौती करने का फैसला नहीं करता। वर्ष 2024–25 में, 50 से ज्यादा देशों से भारत का कुल व्यापारिक वस्तुओं का आयात 720.24अरब डालर था, जबकि निर्यात से सिर्फ 437.42अरब डालर की कमाई हुई, जिससे 282.83 अरब अमेरिकी डालर का व्यापारिक घाटा हुआ।अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए नया तय किया गया फ्रेमवर्क,

जिसमें अगले पांच सालों में 500 अरब डालर का सालाना आयात करने का वायदा किया गया है, भारत ऊर्जा उत्पादन (तेल, एलएनजी, और एलपीजी), कमर्शियल एयर क्राफ्घ्ट और पार्ट्स (खासकर बोइंग से), कोकिंग कोल, कीमती धातुएं, और डेटा सेंटरों के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग इकाइयां (जीपीयू)जैसे हाई–टेक प्रोडक्ट्स पर ध्यान केन्द्रित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस 500अरब डालरके आंकड़ों को श्रूढ़ीवादीश बताया, और कहा कि अगले पांच सालों में भारत की कुल आयात मांग लगभग 2 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सच में बहुत ज्यादा लगता है। बहुत कुछ अर्थव्यवस्था की विकास दर तथा लोगों की क्रय और उपभोग शक्ति पर निर्भर करेगा। इस 500 अरब डॉलर के आंकड़े में मौजूदा ऑर्डर (जैसे पिछले विमान ऑर्डर) और नई खरीद प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं। विडंबना यह है कि भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की 18 फरवरी को भारत–एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा से पहले 114 राफेल लड़ाकू जेट हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ 3.24 लाख करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो यह सौदा भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक होगा, जो मेक–इन–इंडिया ढांचे के तहत भारत–फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा। फ्रांस का नागरिक विमान निर्माता, एयर बस इंडस्ट्री, भारत को यात्री विमानों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारी देरी के कारण, भारत ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ एक मेगा व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने श्सभी सौदों की जननीश के रूप में ब्रांडेड किया। इस डील से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिगत मोड़ मिलेगा। साथ में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता, आतंकवाद के खिलाफ करीबी सहयोग, भारत–प्रशान्त क्षेत्र में मजबूत जुड़ाव और सैन्य क्षमताओं के मिलजुलकर विकास के लिए भी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अब भारत–अमेरिका समझौता, जो काफी हद तक इसी तरह की है, दोनों समझौते के दायरे और आकार को कम करने का खतरा पैदा करता है, जो दो बड़े ट्रेड ब्लॉक, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के व्यापारिक हितों को समायोजित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत दुनिया भर में एक बड़ा व्यापारिक देश नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश की दिलचस्पी अभी भी सीमित है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों से आयात का दबाव भारत के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार घाटे को और बढ़ा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है, जब तक कि भारत द्वारा चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और नीदरलैंड से आयात में काफी कटौती नहीं किया जाता। अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता भारत के सामने मौकों से ज्यादा चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

भारत को अपनी उपलब्धियों को बचाए रखने हेतु एआई के उपयोग की जरूरत

सुश्री रुबल चिब

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर चल रहा विमर्श अब परिपक्व होता जा रहा है। ध्यान अब अमूर्त क्षमता से हटकर व्यावहारिक प्रभाव पर केन्द्रित होता जा रहा है। चर्चा एआई की सैद्धांतिक क्षमता से हटकर व्यवहार में उसके द्वारा हल की जा सकने वाली समस्याओं पर टिकती जा रही है। खाद्य और कृषि जैसे कुछ ही क्षेत्र इस अंतर को इतनी स्पष्टता से दर्शा पा रहे हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां अक्षमताएं मामूली नहीं बल्कि प्रणालीगत हैं और प्रौद्योगिकी को जहां जलवायु, लॉजिस्टिक्स एवं बाजार से जुड़ी गहरी स्थानीय वास्तविकताओं के दायरे में काम करना चाहिए। खाद्य प्रणालियां इस समस्या को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। भारत अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक उत्पादन करता है, फिर भी अनुमानित 68 मिलियन टन भोजन हर साल बर्बाद हो जाता है। इसमें अनियमित आपूर्ति, खराब गुणवत्ता मूल्यांकन और खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कटाई के बाद 35–40 प्रतिशत फल एवं सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। संकट उत्पादन का नहीं, बल्कि रोके जा सकने वाले नुकसान का है। यह नुकसान किल्लत का नहीं, बल्कि पैदावार एवं उपभोग और आंकड़ों एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच के असंतुलन का नतीजा है। सालों से, गुणवत्ता और समय से जुड़ी विश्वसनीय एवं वास्तविक जानकारियों का अभाव भारतीय किसानों तथा नियामकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किया जाता है, तो यह इस खाई को पाटने का एक रास्ता खोलती है। जैविक वास्तविकता और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच की यह खाई ही वह क्षेत्र है जहां व्यावहारिक एआई का खासा कारगर हो सकता है। क्यूजेंस लैब्स में, हमारा काम एक साधारण अवलोकन से शुरू हुआरू अब जबकि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने भुगतान, पहचान और सेवाओं की आपूर्ति को पूरी तरह बदल दिया है, गुणवत्ता का आकलन करने के तरीके के मामले में खाद्य अर्थव्यवस्था काफी हद तक एनालॉग ही बनी हुई है। श्क्यूस्कैनन्य नाम की जो एआई–संचालित संवेदन प्रणाली हमने विकसित की है, वह फलों और सब्जियों में आंतरिक गुणवत्ता संबंधी संकेतों को पकड़ने हेतु अवरक्त (इंफ्रारेड) स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा कृत्रिम सूंघने की क्षमता (आर्टिफीशियल ओल्फैक्शन) का उपयोग करती है और उन्हें निर्णय लेने के समय उपयोगी जानकारियों में परिवर्तित करती है। इरादा स्वचालन को सिर्फ दिखावे की मंशा से लागू करना भर नहीं, बल्कि कम लाभ पर काम करने वाले उपभोक्ताओं, किसानों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अनिश्चितताओं को कम करना था। इस अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि एआई की प्रभावशीलता मूल रूप से संदर्भ पर निर्भर करती है। विदेशी आंकड़े (डेटासेट) या मानकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रशिक्षित मॉडल भारत की उन विविधता भरी परिस्थितियों में विफल हो जाते हैं, जहां फसलों की किस्में, जलवायु, भंडारण की पद्धतियां और बाजार की संरचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल ही अलग–अलग होती हैं। खासकर खाद्य प्रणालियों में, सटीकता को स्थानीयता से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय उपज, भारतीय लॉजिस्टिक्स और भारतीय व्यवहारिक मानदंडों को न समझने वाली एआई के लिए न्यूनतम रूप से अप्रासंगिक और अधिकतम रूप से भ्रामक होने का जोखिम होता है। इसीलिए संप्रभु एवं घरेलू जड़ों में निहित एआई पर वर्तमान नीतिगत जोर सामयिक और जरूरी, दोनों है। श्इंडियाएआई मिशनन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है – इसे रोजमर्रा की वास्तविकताओं से कटे एक अत्याधुनिक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि विकासात्मक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। स्वदेशी एआई अनुप्रयोगों के लिए लक्षित वित्तपोषण, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता में निवेश, भारतीय डेटासेट के लिए समर्थन और क्षेत्र–विशिष्ट समाधानों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए, यह मिशन सक्रिय रूप से एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जहां नवाचार स्थानीय जरूरतों पर आधारित है। स्वदेशी मॉडलों, स्टार्टअप और जनहित की परियोजनाओं का समर्थन करके, यह मिशन अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से लिए गए एआई प्रणालियों के बजाय भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन की गई एआई प्रणालियों के लिए जगह बना रहा है। खाद्य और कृषि के उदाहरणों से साफ होता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से किसानों की आय, खाद्य पदार्थों की कीमतों और पर्यावरण से जुड़े नतीजों पर सीधा असर पड़ता है। बचाई गई उपज की प्रत्येक इकाई भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव को कम करती है, जोकि जलवायु परिवर्तन और जिम्मेदार उपभोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। अक्सर व्यवहार में बदलाव या नए इनपुट की जरूरत वाले उपज बढ़ाने के उपायों के उलट, बेहतर गुणवत्ता मूल्यांकन समन्वय में सुधार करके बेहतर नतीजों को संभव बनाता है – जिससे प्रणाली सही समय पर कार्य करने में सक्षम होती है। समावेशन का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक हित में एआई का सदुपयोग तभी संभव है जब यह सिर्फ बड़े उद्यमों के बजाय छोटे व्यवसायों के लिए भी सुलभ हो। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इसका आशय ऐसे उपकरणों से है जो अनौपचारिक बाजारों में काम करें, स्थानीय भाषाओं का समर्थन करें और मानवीय निर्णय को दरकिनार करने के बजाय उसका पूरक बनें। अस्पष्ट सुझाव थोपने वाली प्रौद्योगिकियां विश्वास अर्जित करने के लिए जूझेंगी। अदृश्य जानकारी को दृश्यमान बनाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली प्रौद्योगिकियों के स्वाभाविक रूप से व्यापक होने की संभावनाएं कहीं अधिक हैं। हमारे देश की राजधानी में 16 से 20 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित होने वाला श्इंडिया एआई इम्पैक्ट समिटय्र ऐसे समय में हो रहा है जब ये अंतर और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, एआई से जुड़ी चर्चाएं शक्तियों के केन्द्रीकरण, डेटा संबंधी विषमताओं और पर्यावरण से जुड़ी कीमतों जैसे मुद्दों से जूझ रही हैं। भारत के लिए मौका एक अलग राह दिखाने में निहित है, एक एक ऐसी राह जहां बुद्धिमत्ता विकेन्द्रीकृत, संदर्भों के प्रति जागरूक और वास्तविक आर्थिक प्रणालियों में समाहित हो। कृषि, खाद्य संबंधी लॉजिस्टिक्स और जलवायु अनुकूलन एआई से जुड़ी कहानी में हाशिए पर नहीं, बल्कि इसके केन्द्र में हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने आप ही प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। इसके लिए विषय–वस्तु की गहरी समझ, जटिल नीतिगत वास्तविकताओं के प्रति धैर्य और सार्वजनिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ समन्वय की जरूरत होती है। हालांकि, जब ये शर्तें पूरी की जाती हैं, तो एआई उन क्षेत्रों को चुपचाप बदल सकता है जिन्होंने लंबे समय से सुधार का विरोध किया है। यह बदलाव व्यवधान के जरिए नहीं, बल्कि पूर्व में लिए गए बेहतर निर्णयों के जरिए होता है।

कूड़ा उठान में सुधार, पर कई जगह रहीं शिकायतें

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम की गोमती नगर केंद्रीय कार्यशाला में नए भवन निर्माण के कारण डीजल पंप बंद किए जाने से प्रभावित हुई कूड़ा उठान व्यवस्था बुधवार को बाहर के पंपों से तेल दिलाए जाने के बाद सुधरी। हालांकि, कुछ जगहों पर समस्या बनी रही। इसकी वजह तेल के लिए लंबी दूरी रही। केंद्रीय कार्यशाला की जमीन पर नगर निगम का नया मुख्यालय बनना है। इस कारण यहां लगा डीजल पंप हटाया जा रहा है। इस वजह से तीन दिन से डीजल की समस्या हो गई। कुछ गाड़ियों को नगर निगम ने प्राइवेट पंपों से डीजल दिलवाया, पर सभी को तेल नहीं मिला। इससे 77 वार्डों में कूड़ा उठान बेपटरी हो गया। इस पर बुधवार को अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। इसके बाद बाहर के पंपों से गाड़ियों को तेल दिलाने का काम तेज हुआ और कूड़ा उठान व्यवस्था सुधरी। हालांकि कई जगहों पर समस्या रही। महात्मा गांधी जियामऊ वार्ड के पार्षद अमित चौधरी ने बताया कि बुधवार को कूड़े का उठान हुआ। भवानीगंज वार्ड के पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद के पति संतोष राय ने बताया कि बुधवार को भी कूड़ा उठान नहीं हुआ।

लंबी दूरी से तेज लेने की वजह से हुई समस्या

नगर निगम की ओर से अभी आशियाना से लगे औरंगाबाद इलाके के पंप से तेल दिलाना शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगम के आठ जोन है और सभी के लिए औरंगाबाद का पंप तय किया गया है। अब इंदिरा नगर और पुराने शहर की गाड़ियां तेल लेने जाएंगी तो आधा तेल इसीमें खर्च हो जाएगा और समय भी ज्यादा लगेगा। इस वजह से कई जोन से तेल लेने ही नहीं गए। मुख्य अभियंता मनोज प्रभात ने बताया कि जोन एक, तीन और सात के लिए बर्लिंग्टन चौराहा के पास पंप से तेल मिलेगा और जोन छह व चार के लिए जोन आठ में औरंगाबाद का पंप तय किया है। दावा किया कि बुधवार को डीजल के चलते कहीं पर कूड़ा उठान में समस्या नहीं आई।

गाड़ियों की मरम्मत में होगी देरी, सफाई पर पड़ेगा असर

सफाई, मलबा उठान आदि की करीब 300 गाड़ियों की मरम्मत का काम अभी गोमती नगर कार्यशाला में ही होता है लेकिन अब यहां नया मुख्यालय बनाने के लिए इसे बंद किया जा रहा है। जिसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ेगा। इस संबंध में बुधवार को केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारी नेताओं ने बैठक भी।

अयोध्या संस्कृति विरासत समिति की बैठक सम्पन्न, सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा नया विस्तार

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।कमिश्नर राजेश कुमार एवं डीआईजी सोमन बर्मा ने डीएम निखिल टीकाराम फुंडे व एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर के साथ अयोध्या संस्कृति विरासत समिति की बैठक आयुक्त सभागार में किया।इस मौके पर सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बैठक के एजेंडे की विस्तार से जानकारी दी।बैठक में अयोध्या धाम में कराई जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभावी एवं नियमित संचालन पर विस्तृत चर्चा की गई।विशेष रूप से राम की पैड़ी तथा नयाघाट पर सायंकाल "साकेत संध्या" एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई।बैठक में मंच, टेंटेज, साउंड सिस्टम, मैनपावर, लाइट एवं साउंड शो की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समिति के पंजीकरण, बैंक खाते के संचालन तथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निरंतर संचालन पर भी विचार–विमर्श हुआ।कमिश्नर ने कहा कि अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा के अनुरूप कार्यक्रमों का स्तर उच्च रखा जाए तथा स्थानीय एवं बाहरी कलाकारों को उचित मानदेय प्रदान कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थित एवं आकर्षक सांस्कृतिक आयोजन कराने के निर्देश दिए।बैठक में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुराज जैन,नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ में एचडीएफसी बैंक का नया करेंसी चेस्ट शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को लखनऊ के विराज खंड में एचडीएफसी बैंक के नए करेंसी चेस्ट का उद्घाटन किया। यह सुविधा उत्तर प्रदेश में बैंक का चौथा और देश में 38वां करेंसी चेस्ट है। इस पहल को प्रदेश में नकदी प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।नव स्थापित करेंसी चेस्ट में उच्च स्तरीय सुरक्षा और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहां पुलिस रूम, कैश रिसीट एरिया, सॉर्टिंग रूम, अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम, वाइब्रेशन एवं मोशन सेंसर सहित मजबूत सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है। उद्घाटन अवसर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के रीजनल डायरेक्टर पंकज कुमार के साथ एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश जवेरी, ग्रुप हेड (डब्ल्यूबीओ ऑपरेशंस) गौरव रॉय, ग्रुप हेड (रीजनल ब्रांच बैंकिंग) अरुण मेदिरत्ता, ब्रांच बैंकिंग हेड (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) मुस्कान सिंह और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैंक के अनुसार यह करेंसी चेस्ट क्षेत्र में नकदी वितरण को अधिक सुचारु और समयबद्ध बनाएगा। इसके माध्यम से लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर और कानपुर जिलों में स्थित 246 शाखाओं और 317 एटीएम को निर्बाध नकदी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे करेंसी नोटों की उपलब्धता के लिए टर्न–अराउंड–टाइम में सुधार होगा और व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय नागरिकों को बेहतर कैश मैनेजमेंट का लाभ मिलेगा।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा द्वितीय बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगितादृ2026 का आयोजन भव्य एवं गरिमामय स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की 36 टीमों ने पंजीकरण कराया है, जो इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाता है।यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण एवं विधि विभागाध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा के निर्देशन में आयोजित की जा रही है। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्घाटन 13 फरवरी को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।उद्घाटन दिवस पर ड्रा ऑफ लॉट्स, रिसर्चर टेस्ट एवं वर्चुअल उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण 14 फरवरी से शुरू होंगे, जिनमें प्रतिभागी टीमें अपनी वकालत कौशल, शोध क्षमता और न्यायालयीन प्रस्तुतीकरण का प्रदर्शन करेंगी।राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता विधि छात्रों को व्यावहारिक अधिवक्ता कौशल विकसित करने, शोध दक्षता सुदृढ़ करने और न्यायालयीन कार्यप्रणाली की गहन समझ प्राप्त करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।

महिला, किसान और युवाओं पर केंद्रित है यूपी का बजट : प्रो. मानस पाण्डेय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष का बजट महिला सुरक्षा, किसान कल्याण और युवाओं के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस मामले पर हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि से गुरुवार को बात करते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मानस पाण्डेय ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के संतुलित एवं समग्र आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छोटे–छोटे कार्यों हेतु ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की है, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिला किसानों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल है। प्रो. पाण्डेय ने बताया कि युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। इससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार के क्षेत्र में एमएसएमई और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, जो युवाओं की सबसे बड़ी चिंता को दूर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को आगे बढ़ाने तथा निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सरल और सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य को निवेश के अनुकूल बनाएगी। शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों को स्मार्ट एवं आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित करने तथा शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं किसानों के लिए कुसुम योजना का प्रावधान कर उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर उद्यमिता की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। प्रो. मानस पाण्डेय ने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और विकास के संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो प्रदेश को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा।

शीतला चौकिया धाम के सुंदरीकरण का कार्य शुरू, छह करोड़ की लागत से बदलेगा स्वरूप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, । यूपी के जौनपुर स्थित पूर्वांचल में आस्था का प्रमुख केंद्र मां शीतला चौकिया धाम अब धार्मिक स्थल के साथ–साथ पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से मंदिर परिसर के सुंदरीकरण कार्य की शुरुआत गुरुवार से कर दी। गुरुवार को मंदिर प्रांगण के बरामदे पर लगे टीनशेड को श्रमिकों द्वारा हटाया गया। इसके बाद बरामदे को तोड़कर उसे नव्य और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। मंदिर के मुख्य द्वार को नए डिजाइन में निर्मित किया जाएगा, जिस पर मां शीतला की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। द्वार के दोनों ओर भी मां शीतला के चित्र लगाए जाएंगे, जबकि प्रवेश द्वार पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार नक्शे के अनुरूप पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे मंदिर का अग्रभाग अधिक स्पष्ट, भव्य और आकर्षक दिखाई देगा। मंदिर के पीछे स्थित सरोवर में दो नए फव्वारे लगाए जाएंगे तथा पूर्व से स्थापित एक फव्वारे की मरम्मत कर उसे पुनः संचालित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने हेतु सीटिंग एरिया विकसित किया जाएगा। सरोवर के चारों ओर तथा दीवारों पर आध्यात्मिक चित्रों एवं डिजाइनिंग स्टोन की आकर्षक सज्जा की जाएगी। धाम की गलियों में इंटरलॉकिंग द्वारा सीसी मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही एक शुलभ शौचालय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंच का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा। परिसर में दो नए प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। एक प्रवेश द्वार शाहगंज मार्ग की ओर तथा दूसरा पचहटिया–शीतला चौकिया मार्ग पर विकसित किया जाएगा। सुंदरीकरण कार्य प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। उम्मीद जताई जा रही है कि कार्य पूर्ण होने के बाद शीतला चौकिया धाम धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी विशेष पहचान बनाएगा।

संक्षिप्त खबरें

मछली मंडी के सामने भीषण सड़क हादसा, इको वैन और ट्रैक्टर–ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। रात्रि थाना क्षेत्र में मछली मंडी के सामने इको वैन और ट्रैक्टर–ट्रॉली के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा–तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया।प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में थाना स्थानीय पर सूचना मिली कि मछली मंडी के सामने एक इको वैन और ट्रैक्टर–ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई है। सूचना पर पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जांच में सामने आया कि इको वैन संख्या न्च77फ1222, जो मछलियों से भरी हुई थी, को सामने से आ रही ट्रैक्टर–ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इको वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों की पहचान संजय सिंह (27 वर्ष) पुत्र वीरेन्द्र सिंह, पप्पू कश्यप (60 वर्ष) पुत्र छोटा, हर्ष सिंह (19 वर्ष) पुत्र पप्पू सिंह तथा पप्पू सिंह (50 वर्ष) पुत्र रामजीत सिंह, निवासीगण मैथा, जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई है। सभी को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से ट्रामा सेंटर भेजा गया।ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान संजय सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। हर्ष सिंह की हालत गंभीर होने पर परिजनों द्वारा उन्हें ट्रामा सेंटर से वेदांत अस्पताल ले जाया गया, जहां वे वेंटिलेटर पर हैं। शेष दो घायलों का ट्रामा सेंटर में उपचार जारी है।

'महोबा सूर्य महोत्सव' से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान

लखनऊ, (संवाददाता)।उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 'महोबा सूर्य महोत्सव' का शुभारंभ 11 फरवरी से हो गया है। 17 फरवरी तक चलने वाला यह सात दिवसीय महोत्सव सूर्य के सात रंगों की अवधारणा पर आधारित है, जो ऊर्जा, बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वीरता का प्रतीक है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य महोबा स्थित प्राचीन रैहेलिया सूर्य मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।महोत्सव का शुभारंभ रैहेलिया सागर तट स्थित सूर्य मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान सूर्य की आरती के साथ हुआ। इसके बाद सूर्य मंदिर से मोदी ग्राउंड तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।महोत्सव का प्रमुख आकर्षण पहली बार आयोजित तारामंडल प्रदर्शनी है, जो 11 से 14 फरवरी तक चलेगी। इसमें दूरबीन से ग्रह–दर्शन, वर्चुअल रियलिटी अनुभव और विशेष सोलर फिल्टर से सूर्य दर्शन की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।मोदी ग्राउंड में 11 से 17 फरवरी तक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

आशियाना में बंधन बैंक की नई शाखा का शुभारंभ, विवेकानंद प लीक्लिनिक को उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट

लखनऊ, (संवाददाता)। बंधन बैंक ने बुधवार को आशियाना, लखनऊ में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। शाखा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं सीबीओ राजिंदर कुमार बब्बर तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम एवं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नई शाखा के उद्घाटन के साथ ही बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एक उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी दान की। एम्बुलेंस की चाबी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजिंदर कुमार बब्बर ने स्वामी मुक्तिनाथानंद को सौंपते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया।बंधन बैंक ने कहा कि शाखा नेटवर्क के निरंतर विस्तार से स्पष्ट है कि बैंक विविधीकरण और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर जोर दे रहा है। आशियाना में नई शाखा खुलने से स्थानीय ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा और उन्हें नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान उपलब्ध होंगे। इस विस्तार के साथ बैंक उत्तर प्रदेश में 560 शाखाओं के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से 32 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है, जबकि देशभर में इसकी 6,490 से अधिक शाखाएं संचालित हैं।कार्यकारी निदेशक एवं सीबीओ राजिंदर कुमार बब्बर ने कहा कि बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहा है ताकि उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि आशियाना में नई शाखा की शुरुआत बैंक की इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसआर पहलों के माध्यम से बैंक आपात चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न समुदायों को सेवा देने वाले अस्पतालों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जरूरत के समय लोगों को समय पर उपचार मिल सके।बंधन बैंक ने अपनी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभर में कुल 18 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दान की हैं।

रहीमाबाद–दिलावरनगर रेलखंड पर दर्दनाक हादसा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में दो युवतियों की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 11रू25 बजे स्टेशन अधीक्षक, उत्तर रेलवे, रहीमाबाद द्वारा थाना रहीमाबाद पर लिखित सूचना दी गई कि डाउन बॉक्स एन ट्रेन के चालक ने रहीमाबाद और दिलावरनगर रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर संख्या 1106ध्18–1106ध्16 पर एक रेल दुर्घटना होने की जानकारी दी है। चालक द्वारा दी गई सूचना में बताया गया कि ट्रैक पर दो युवतियां ट्रेन की चपेट में आ गई हैं।सूचना प्राप्त होते ही थाना रहीमाबाद की पुलिस तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान नीतू (23 वर्ष) पुत्री बुद्धा तथा शशी (20 वर्ष) पुत्री अशर्फी लाल निवासी ग्राम मनकौटी, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ के रूप में हुई। दोनों युवतियों की ट्रेन से कट जाने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई।घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां माहौल अत्यंत भावुक और गमगीन हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की और नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस द्वारा घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना दुर्घटनावश हुई ।

9.12 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान, विकास, रोजगार और अवसंरचना पर विशेष जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये का विशाल बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2025–2026 के 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये के अनुमान से 1 लाख 3 हजार 960 करोड़ 29 लाख रुपये अधिक है, जो लगभग 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने इस बजट को किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास को समर्पित बताया है।बजट में 6 लाख 64 हजार 470 करोड़ 55 लाख रुपये राजस्व व्यय तथा 2 लाख 48 हजार 225 करोड़ 80 लाख रुपये पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय में से 1 लाख 77 हजार 744 करोड़ 12 लाख रुपये परिसंपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे, जिससे रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कुल अनुमानित प्राप्तियां 8 लाख 48 हजार 233 करोड़ 18 लाख रुपये हैं, जबकि 43 हजार 565 करोड़ 33 लाख रुपये की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं।कृषि और किसान कल्याण को बजट में प्रमुख स्थान दिया गया है। अब तक 3 लाख 4 हजार 321 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो पूर्ववर्ती 22 वर्षों से 90 हजार 802 करोड़ रुपये अधिक है। पेराई सत्र 2025–2026 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ किसानों को मिलेगा। गेहूं, धान और बाजरा की रिकॉर्ड खरीद के साथ किसानों को हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ किसानों को 94 हजार 668 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। फसल बीमा, सोलर पंप, सीड पार्क, प्राकृतिक खेती और एग्री एक्सपोर्ट हब जैसी योजनाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है।महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत बीसी सखी मॉडल, महिला सामर्थ्य योजना, मिशन शक्ति, सेफ सिटी परियोजना और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसी पहलें जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है।युवाओं और रोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास मिशन के माध्यम से 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 4.22 लाख को रोजगार मिला है। अभ्युदय योजना के 163 केंद्रों पर 23 हजार से अधिक युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। 49 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। पुलिस विभाग में 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां की गई हैं और बड़ी संख्या में पदोन्नति भी दी गई है। मनरेगा के तहत 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं।स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 14 हजार 997 करोड़ रुपये तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 37 हजार 956 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। एमबीबीएस और पीजी सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए भी हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।अवसंरचना और औद्योगिक विकास के लिए 27 हजार 103 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सड़कों और सेतुओं के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए 34 हजार 468 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 18 हजार 290 करोड़ रुपये तथा नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22 हजार 676 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65 हजार 926 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के लिए 2 हजार 104 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।शहरी विकास और आवास के लिए 7 हजार 705 करोड़ रुपये तथा नगर विकास के लिए 26 हजार 514 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास के लिए 750 करोड़ रुपये तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कुल 2 हजार 111 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास, संग्रहालयों की स्थापना और पर्यटन अवसंरचना को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में प्रदेश में 122 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया।ग्राम्य विकास के लिए 25 हजार 500 करोड़ रुपये तथा पंचायती राज के लिए 32 हजार 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 67 प्रतिशत अधिक है। डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन, ग्रामीण स्टेडियम और आवास योजनाओं को भी गति दी जाएगी। सृजन पर केंद्रित एक व्यापक विकास दस्तावेज के रूप में सामने आया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।

दिल्ली दरवाजा में बनेगा पार्क,कच्चा नाला को पक्का बनवाने का वादा

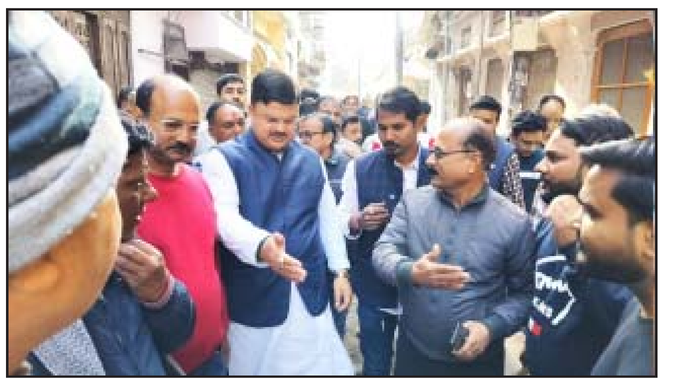

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।नगर की सरकार आपके द्वार अभियान के तहत महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने विक्रमादित्य वार्ड का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नजूल की खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनवाने एवं कच्चा नाला को पक्का बनवाने का वादा किया।सुबह के लगभग साढ़े आठ बजे महापौर व नगर आयुक्त गुदड़ी बाजार तिराहा पहुंचे तो पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र मिश्र ने स्थानीय नागरिकों के साथ फूल–मालाओं से उनका स्वागत किया। यहां स्थानीय नागरिकों ने बंगालीहाता के पास नाली की सफाई एवं रोड लाइट जलवाने की मांग की। महापौर ने इस पर अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। पार्षद प्रतिनिधि ने सीवर डलवाने का मुद्दा उठाया। थोड़ा आगे बढ़ने पर कार्नर पर स्थित जर्जर भवन में लटके तार बदलवाने की मांग सामने आई तो महापौर ने बिजली विभाग से पत्राचार करने का भरोसा दिया। महापौर ने रास्ते में लगे इंडिया मार्का–टू हैंडपंप को चलवाकर जांच की तो नल सही पाया गया। नालियों में एंटीलार्वा का छिड़काव चल रहा था। सफाई कर्मियों को ठेले से कूड़ा उठाता देख महापौर ने संतोष जताया।अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव की गली के सामने खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण कर पार्क बनवाने एवं हाईमास्ट लाइट एवं लोगों के बैठने के लिए बेंच लगवाने की मांग पर महापौर ने जल्द कदम उठाने का वादा किया। उन्होंने दिल्ली दरवाजा ढाल पर सड़क सही करवाने का भरोसा दिया। इस दौरान लोगों ने पेयजल संकट से महापौर को अवगत कराया। राजेश निषाद के आवास के पास नाले पर स्लैप डलवाने का भी वादा महापौर ने किया। इस दौरान कच्चा नाला को पक्का बनवाने, परिक्रमा मार्ग को जल्द पूरा कराने की आवश्यकता जताई गई।भ्रमण के दौरान विघ्नेश्वरनाथ महादेव के पास गंदगी देखकर नाराजगी जताई और सफाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने क्रॉसिंग एवं नालियों पर टूटी हुई पटिया ठीक करने का भरोसा दिया। दिल्ली दरवाजा में एक जगह बिजली का खंभा टेढ़ा होने पर नगर आयुक्त ने नए खंभे पर तारों के स्थानांतरण कराने के लिए पत्राचार का निर्देश अधिकारियों को दिया। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि महापौर ने भ्रमण के दौरान लोगों के घरों में सप्लाई हो रहे पेयजल की जांच कराई। पानी का टीडीएस सामान्य पाया गया। जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए अवशेष क्लोरीन भी पानी में पाया गया। निरीक्षण के दौरान पार्षद सुनील यादव, अपर आयुक्त भारत भार्गव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, महाप्रबंधक जलकर सौरव श्रीवास्तव,निर्माण खंड के सहायक अभियंता राजपति यादव, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, रवि सोनकर, आलोक द्विवेदी, पूर्व पार्षद दिलीप जायसवाल, मदन पहलवान, अमीरचंद जायसवाल आदि थे।

बिछुड़ी बुजुर्ग महिला को परिजनों से मिलाया

अयोध्या। महिला थाना पुलिस ने परिवार से भटकी एक बुजुर्ग महिला को उसके परिजनों से मिला कर सराहनीय कार्य किया।इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को करीब 10रू30 बजे पीआरबी 0938 पर तैनात उप निरीक्षक आनंद दिक्षित तथा महिला कांस्टेबल ज्योति यादव व पूजा ने अपने परिवार से बिछड़ कर आई बुजुर्ग महिला विमला देवी पत्नी राम जी गुप्ता उम्र 67 वर्ष निवासी शारदा पुरम् कालोनी उसरू को महिला

थाना लेकर आए।उन्होंने बताया कि पहले तो बुजुर्ग महिला अपने परिजनों का मोबाइल नंबर या पता बताने में समर्थ दिखाई दे रही थी लेकिन महिला पुलिस कर्मियों के काफी देर तक व शालीनता से पूछताछ में उसने पता बताया।उसके द्वारा बताए गए पते पर दूरभाष के माध्यम से बुजुर्ग महिला के बेटा दुर्गेश गुप्ता पुत्र राम जी गुप्ता निवासी शारदा पुरम कॉलोनी उसरू महिला थाना परिसर आए।जहां पर उक्त महिला को सकुशल उनके पुत्र को सौंप दिया गया।बुजुर्ग महिला के परिजनों ने महिला थाना पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा किया।

संक्षिप्त खबरें

विजेथुआ में 14 से 17 फरवरी तक चार दिवसीय विराट किसान मेला होगा आयोजित

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर । जनपद के विजेथुआ महावीरन, सूरापुर में 14 से 17 फरवरी 2026 तक चार दिवसीय पारंपरिक विराट किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कृषि से जुड़े सहयोगी विभाग भी अपने–अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं कृषि विशेषज्ञ किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक व रसायन निर्माता कंपनियां भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर जानकारी देंगी।

'पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर शादी का झांसा देकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश'

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर । धनपतगंज पुलिस ने पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर शादी का झांसा देकर वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जेवरात व नकदी बरामद की है। राजस्थान के करौली निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपने बेटे की शादी के लिए देवरिया गया था। विवाह के बाद 10 फरवरी की शाम करीब आठ बजे माइलस्टोन 110 स्थित कैंटीन के पास वाहन रुकवाकर 64 हजार रुपये की मांग की गई। आरोप है कि रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई। भयवश सात हजार रुपये मौके पर दे दिए गए। बाद में पीड़ित ने

धनपतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर गठित टीम ने बेनीपुर अंडरपास के पास से सुनील कुमार, मुस्कान उर्फ सुमन उर्फ प्रियंका, शशि भारती और रानी निशा को गिरफ्तार कर लिया। सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपितों के कब्जे से दो पायल, चार बिछिया, एक मंगलसूत्र, एक लाकेट और 19,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

वांछित को पकड़ने गयी एसओजी एवं पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में गुरुवार की रात्रि वांछित को पकड़ने गयी एसओजी टीम एवं पुलिस वाहन पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हमले की सूचना पर पहुँचे बक्शा थानाध्यक्ष के वाहन को भी ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उच्चाधिकारियों के आदेश पर करीब आधा दर्जन थानों की फोर्स ने गांव में पहुँच घेराबंदी कर रहें है। सिकरारा थाने के इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह एसओजी टीम के साथ रात करीब साढ़े नौ बजे बक्शा थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव की अनुसूचित बस्ती में एक वांछित पंकज गौतम की गिरफ्तारी के लिए पहुँचे थे तभी ग्रामीणों ने एसओजी टीम एवं पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर से हमला कर दिए। हमले में एसओजी सिपाहियों के अलावा सिकरारा थाने के एक उपनिरीक्षक विनोद सिंह के घायल होने की खबर है। उधर सूचना पर पहुँचे बक्शा थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के वाहन का सीसा टूट गया। बवाल की सूचना पर करीब आधा दर्जन से अधिक थानों की फोर्स पहुँच बस्ती को घेर लिया है।

रेलवे मजदूर यूनियन का भंडारी जंक्शन पर प्रदर्शन, श्रम कानून व निजीकरण के विरोध में बांधी काली पट्टी

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 13 फरवरी। यूपी के जौनपुर स्थित भंडारी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, जौनपुर शाखा के तत्वावधान में सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व शाखा मंत्री राकेश सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जताई। यूनियन ने 26 श्रम कानूनों को समाप्त कर लागू किए गए आईआर कोड एवं अन्य लेबर कोड का विरोध किया। साथ ही नई पेंशन योजना (छच्ै) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (न्च्ै) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (व्च्ै) लागू करने की मांग उठाई। यूनियन ने सरकारी विभागों में निगमीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने का भी विरोध किया। शाखा मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कथित 'काले कानून' वापस नहीं लिए गए तो यूनियन अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आगे भी व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने एकजुटता के साथ अपनी मांगों को दोहराया।

फायर विभाग को जून माह तक मिल जाएगा अपना कार्यालय व आवास

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। इसी वर्ष जून माह के अंतिम सप्ताह तक फायर विभाग को पुलिस लाइन परिसर में खुद का चार यूनिट का कार्यालय के साथ–साथ आवास

भी मिल जाएगा इस बात की जानकारी देते हुए सीएफओ एमपी सिंह ने बताया 4 करोड़ 74 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए मुख्यालय द्वारा मुहैया कराया गया था।जिस पर बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंतिम सप्ताह तक फायर विभाग को अपना कार्यालय, आवास, गैराज मिल जाएगा।उन्होंने बताया इसका निर्माण आवास विकास परिषद संस्था द्वारा कराई जा रही है।सीएफओ एमपी सिंह ने बताया कि फायर विभाग का यह कार्यालय चार यूनिट की होगी,जिसमें एक सीएफओ का कक्ष,एक अग्निशमन अधिकारी का कक्ष,एक अग्नि शमन विभाग का कार्यालय,एक नियंत्रण कक्ष के साथ फायर विभाग के वाहनों को खड़ी करने के लिए गैराज का भी निर्माण भी हो रहा है।बताया कि फायर कर्मियों के रहने के लिए पर्याप्त संख्या मे अत्याधुनिक बैरक का निर्माण होगा। यहां पर निर्माण होने के चलते पिछले कुछ महीनो से फायर विभाग के बड़े व छोटे वाहन के साथ–साथ फायर कर्मियों को राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है फायर टेंडर सहित अन्य सभी वाहनों को राजकीय इंटर कालेज परिसर मे शिफ्ट किया गया है।बताते चलें कई दशकों से पुलिस लाइन परिसर में स्थित टीन के नीचे ठंडी, गर्मी व बरसात में फायर विभाग के कर्मी रह रहे थे।पिछले वर्ष महानिदेशक फायर विभाग ने निरीक्षण के दौरान यह दशा देखकर इसे ठीक करने का निर्णय लिया और इसके निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए साथ ही साथ पत्राचार के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह को निर्देश दिए थे।जिसके चलते अब कई वर्षों बाद फायर विभाग को चार यूनिट का अपना कार्यालय, बैरक इसी वर्ष जून माह तक मिल जाने की उम्मीद है।

राम की नगरी में आने वाले भक्तों का स्वागत करेगा लक्ष्मण द्वार,पिंक सॉलिड स्टोन से सजेगा प्रवेश द्वारा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। राम की नगरी अब भक्तों के लिए और अधिक आकर्षक व स्वागतमय बन रही है।राम मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करने के लिए एनएच–330ए (अयोध्या–गोण्डा मार्ग) पर एक शानदार लक्ष्मण द्वार का निर्माण तेजी से चल रहा है।यह प्रवेश द्वार अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और निखारने के साथ–साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।यह भव्य लक्ष्मण द्वार देईपुरध्कटरा भागचंद्र' अहतमाली क्षेत्र में 40 मीटर चौड़े मार्ग पर बनाया जा रहा है।उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।कुल निर्माण लागत 3,970.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।द्वार को पिंक सॉलिड स्टोन से सजाया जाएगा, जो इसे राजसी एवं आकर्षक बनाएगा। पिंक स्टोन का उपयोग न केवल सौंदर्य बढ़ाएगा, बल्कि यह स्थानीय शिल्प कौशल को भी प्रदर्शित करेगा और अयोध्या की प्राचीन वास्तुकला से प्रेरित होगा। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र यादव ने बताया कि वर्तमान में परियोजना का 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अक्टूबर तक पूरा लक्ष्मण द्वार तैयार हो जाएगा।लक्ष्मण द्वार के बनने से यह मार्ग धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी बन जाएगा। रामायण काल में लक्ष्मण जी के भाई राम के प्रति समर्पण की याद दिलाता यह द्वार भक्तों के मन में श्रद्धा एवं उत्साह का संचार करेगा। अयोध्या विकास की इस नई परियोजना से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का धार्मिक पर्यटन नक्शा और चमकदार हो रहा है।सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में धार्मिक स्थलों का विकास एवं पर्यटन संवर्धन प्रमुख स्थान रखता है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद यहां पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लक्ष्मण द्वार का निर्माण इसी दिशा में एक और कदम है, जो न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। स्थानीय व्यापारियों, होटलों, परिवहन सेवाओं और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एनएच–330ए पर यह लक्ष्मण द्वार अयोध्या–गोण्डा मार्ग की गरिमा को कई गुना बढ़ा देगा।

चौदह कोसी मार्ग चौड़ीकरण में अफसरों की मिलीभगत से नहीं हट रहा अतिक्रमण

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। अयोध्या के विकास और श्रद्धा की प्रतीक चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मिलीभगत का काला साया मंडराने लगा है। शासन की प्रमुख प्राथमिकता वाली इस योजना में अवैध निर्माण और सरकारी नाले पर किए गए अतिक्रमण को लेकर अब सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उच्चाधिकारियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद धरातल पर कार्रवाई शून्य है, जिससे न केवल परियोजना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, बल्कि सरकारी तंत्र की मंशा पर भी संदेह गहरा गया है।प्रकरण की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड–3) के अधिशासी अभियंता ने जनवरी 2025 में ही लिखित आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि परिक्रमा मार्ग की परिधि में आने वाले बाधक भवनों को हटाया जाना अनिवार्य है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, महीनों बीत जाने के बाद भी बुलडोजर खामोश है।इस प्रशासनिक शिथिलता के पीछे भ्रष्ट तत्वों और अधिकारियों की गहरी साठगांठ की आशंका जताई जा रही है। हद तो तब हो गई जब उप जिलाधिकारी सदर द्वारा कथित तौर पर यह बयान दिया गया कि 'जो हो गया, वो हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा'कृयह वक्तव्य न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत है, बल्कि अवैध कब्जा करने वालों को खुलेआम संरक्षण देने का प्रमाण भी माना जा रहा है।सबसे चिंताजनक पहलू सरकारी नाले पर किया गया अवैध निर्माण है। अतिक्रमणकारियों ने जल निकासी के मुख्य स्रोत को ही अवरुद्ध कर दिया है, जिससे भविष्य में भीषण जलभराव का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अधिकारियों की यह 'मौन स्वीकृति' सीधे तौर पर शासन की छवि को धूमिल कर रही है और विकास कार्यों के नाम पर कागजी खानापूर्ति का संकेत दे रही है।अयोध्या की गरिमा और परिक्रमा मार्ग की पवित्रता को देखते हुए अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई, विजिलेंस या किसी विशेष जांच दल (एस आई टी) से कराने की मांग जोर पकड़ रही है।मांग की गई है कि सरकारी नाले और अधिग्रहित भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए और विकास कार्य में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो अयोध्या का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता है। जनता अब मुख्यमंत्री से न्याय की आस लगाए बैठी है ताकि अयोध्या के विकास पथ से अतिक्रमण का यह कलंक मिट सके।

संक्षिप्त खबरें

पीयू के इनक्यूबेटी "हीथोक्स" को फाइजर से 60 लाख रुपये का अनुदान

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एलुमनाई एवं इनोवेशन सेंटर के इनक्यूबेटी "हीथोक्स प्राइवेट लिमिटेड" को फाइजर की हेल्थकेयर इनोवेशन योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह अनुदान सिकल

सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान (म्ंतसल क्मजमबजपवद) के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को बात करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो वंदना सिंह ने बताया कि यह अनुदान 12 फरवरी 2026 को वाणिज्य भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित "मेडटेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप शोकेस" प्रदर्शनी के दौरान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीपीआईआईटी (क्च्प्प्ज) के अंतर्गत किया गया था। इस प्रदर्शनी में देशभर से प्राप्त 300 आवेदनों में से केवल 08 स्टार्टअप्स का चयन किया गया, जिनमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इनक्यूबेटी "हीथोक्स प्राइवेट लिमिटेड" को भी चयनित किया गया। फाइजर इंडोनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप को यह अनुदान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रदान किया गया। "हीथोक्स प्राइवेट लिमिटेड" की ओर से संस्थापक निदेशक शेखर आनंद (शोध निर्देशक), कुसुम आनंद, प्रिया काकरान एवं उनकी टीम उपस्थित रही। साथ ही विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के शिक्षक डॉ. मनीष कुमार गुप्ता (सह–मुख्य शोधकर्ता) भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में स्टार्टअप इंडिया के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल, संयुक्त सचिव श्री संजीव, प्रो. शैलेंद्र सराफ (निदेशक, नाइपर अहमदाबाद), दीपक बागला (मिशन डायरेक्टर, अटल इनोवेशनकृनीति आयोग) तथा सुश्री मिनाक्षी नेवतिया (मैनेजिंग डायरेक्टर) उपस्थिति रही।

चारों आरोपी 14 दिन की रिमांड पर

भदोही, (संवाददाता)। आशीष यादव हत्याकांड के चारों आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को सीजेएम आशीष कुमार मिश्रा की कोर्ट में पेश किया। पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिल गई। चारों को जेल भेजा गया है। वहीं, दूसरे पक्ष की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। करीब दो घंटे तक न्यायालय में गहमागहमी की स्थिति बनी रही। सीओ औराई राजीव कुमार सिंह के आश्वासन पर अधिवक्ता शांत हुए। औराई के बनपुरवा जंगला गांव में मंगलवार को जमीन के विवाद में गोली मारकर आशीष यादव की हत्या कर दी गई थी।

कचेहरी परिसर मे बम होने की धमकी से पूरे दिन छावनी मे तब्दील रहा कचेहरी परिसर

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।शुक्रवार को कचेहरी को बम से उडाने की धमकी को लेकर पूरा कचेहरी परिसर छावनी मे तब्दील रहा।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ, बीडीएस, और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रही।वही एहतियातन तौर पर पूरे कचहरी परिसर को तुरंत खाली कराया गया।धमकी की सूचना मिलते ही सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी, वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली नगर प्रदीप कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने आम लोगों और अधिवक्ताओं को सुरक्षित बाहर निकाला।इस मौके पर पुलिस,खूफिया तंत्र, सीआरपीएफ व बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड के माध्यम से कचहरी के विभिन्न भवनों, अदालत कक्षों और संवेदनशील हिस्सों की सघन तलाशी लिया गया।इस मौके पर पुलिस लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से सहयोग की अपील करती हुई दिखाई दी।सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और परिसर में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तैनात कर आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई।इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर सभी वकीलों से अपील की गई है, जब तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तब तक कोई परिसर में ना जाएं।कोर्ट में बम होने की खबर मिली है।परिसर खाली करने के एनाउंसमेंट पर वकील अपने चौंबरों से बाहर आ गए।कोर्ट रूम–परिसर खाली हो गया है।फिलहाल हो सकता है कि अफवाह हो, लेकिन कभी भी कोई भी घटना हो सकती है।इसलिए हम सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने बताया कि जिसने भी ईमेल किया उसने खासकर जज व अधिवक्ता को टारगेट बनाया है। उन्होंने बताया कि जो भी यह मेल भेजा है उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाई करने की मांग प्रशासन से की जायेगी।वही सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि सूचना की हर तरफ से बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल एहतियात के तौर पर कचहरी परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया।सूचना की सत्यता की पुष्टि के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।जिसके बाद दोषियो के खिलाफ कार्यवाई की जायेगी।

जलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय मछलीशहर का आकस्मिक निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर 13। जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र के द्वारा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी मछलीशहर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यालय में विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि पत्रावलियों का उचित ढंग से रख–रखाव किया जाए। उन्होने पाया कि कार्यालय में स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिस पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि परिसर को सुंदर एवं आदर्श ब्लॉक के रूप में विकसित करने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। न्होने परिसर में स्थित निस्प्रयोज्य भवनों का भी अवलोकन करते हुए निर्देशित किया कि संबंधित निस्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरणध् निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराई जाए तथा तत्पश्चात नीलामी की प्रक्रिया संपन्न कर उक्त भूमि का उपयोग अन्य जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी में प्रस्तावित सभागार के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और ही यह विकासखंड आकांक्षात्मक ब्लॉक के अंतर्गत चयनित है, इसलिए आकांक्षात्मक ब्लॉक के निर्धारित पैरामीटरों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाने हेतु खंड विकास अधिकारी को निर्देशित भी किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत संरचना एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित मानकों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होने महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित "प्रेरणा कैंटीन" का भी अवलोकन किया। उन्होंने कैंटीन की स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित संचालन की प्रशंसा की तथा वहां तैयार की गई चाय का स्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार संचालित इस प्रकार की पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का ग्रामीण विकास में योगदान सराहनीय है, जो भविष्य में गांवों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।